

विधानसभा होगी डिजिटल: विधायकों के सवालों की प्रक्रिया ऑनलाइन



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों के सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाएं और याचिकाएं अब डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को इसका शुभारंभ किया। प्रशिक्षण 30 अक्टूबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पहले

विधायकों को लिखित प्रश्न जमा करने पड़ते थे, जिससे एक सत्र में औसतन 700 प्रश्न आते थे। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़कर करीब चार हजार हो गई है। ये प्रश्न विधायकों के क्षेत्रों की समस्याओं को सामने लाते हैं। इनके प्रभावी निराकरण के लिए व्यवस्थाओं को सक्षम बनाना आवश्यक है।

पांच बैच में होगा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायकों को पांच

बैच में बांटा गया है। प्रत्येक बैच में करीब 50 विधायक शामिल हैं। मंत्रियों, विधायकों के साथ उनके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों और निजी सहायकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस दौरान नेवा एप्लीकेशन से ऑनलाइन प्रश्न लगाने, जवाब देखने और विधायी सूचनाएं प्रस्तुत करने की जानकारी दी जा रही है। व्यवस्था लागू होने पर प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, संकल्प और याचिकाएं ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकेंगी।

कार्यसूची, विधेयक, प्रश्नों के उत्तर और सदन की कार्यवाही भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी।

श्री तोमर ने कहा कि तकनीक से कामकाज में समय की बचत, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। नेवा के माध्यम से विधानसभा को डिजिटल मंच पर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इससे विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठाने और संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

शाजापुर जिले के ग्राम रंथभंवर में हेलीकॉप्टर की सहायता से संचालित ...

कृष्णमृग और नीलगाय रेस्क्यू अभियान का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को शाजापुर जिले के ग्राम रंथभंवर में हेलीकॉप्टर की सहायता से संचालित कृष्णमृग और नीलगाय रेस्क्यू अभियान के दूसरे चरण का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. यादव ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका की विशेष टीम की सहायता से बोमा पद्धति के माध्यम से वन्यजीवों को सुरक्षित पकड़कर निर्धारित वन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। नौ अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दूसरे चरण में दो हजार कृष्णमृगों के स्थानांतरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक शाजापुर जिले से 1,236 से अधिक कृष्णमृगों और नीलगायों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है।

रेस्क्यू किए गए कृष्णमृगों को श्योपुर के जंगलों, गांधी सागर और रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट सहित निर्धारित वन क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। इनके सुरक्षित परिवहन के लिए 11 ट्रकों की व्यवस्था की गई है। साथ ही पशु चिकित्सकों, आवश्यक उपकरणों और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री



ने कहा कि हेलीकॉप्टर की सहायता से बोमा पद्धति पर आधारित यह अभियान दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला

प्रयास है। इससे वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वन विभाग

और प्रशासनिक टीम के प्रयासों की सराहना की तथा अभियान की प्रगति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

डीजीपी मकवाणा 30 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। गृह विभाग ने उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख निर्धारित करते हुए बुधवार को आदेश जारी कर दिया। नए डीजीपी एक दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे।



► **एक दिसंबर को नए डीजीपी की ज्वाइनिंग**
► **चयन के लिए यूपीएससी को भेजे गए 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम**

में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 30 नवंबर की तारीख तय की गई।

नए डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं। यूपीएससी तीन

अधिकारियों का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा, जिसके आधार पर नए डीजीपी का चयन होगा।

संभावित नामों में जेल महानिदेशक वरुण कपूर, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक उपेंद्र जैन और होमगार्ड महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। वरुण कपूर ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। यदि मकवाणा की सेवानिवृत्ति एक दिसंबर के बाद होती, तो कपूर की दावेदारी प्रभावित हो सकती थी, क्योंकि डीजीपी पद के लिए अधिकारी की सेवानिवृत्ति में कम से कम छह महीने शेष होना आवश्यक है। वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर आईपीएस पंकज श्रीवास्तव का नाम भी चर्चा में था।

श्रीवास्तव आनंद संस्थान के सीईओ नियुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने दो सेवानिवृत्त अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सेवानिवृत्त आईएसएस अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव को राज्य आनंद संस्थान का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार हिंगनकर की मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर

प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करेगा। श्री श्रीवास्तव शिवपुरी और रीवा सहित कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने गृह विभाग के सचिव, आवकारी आयुक्त और जनसंपर्क आयुक्त की जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। वे अपनी पत्नी के साथ नर्मदा परिक्रमा पूरी कर चुके हैं और साहित्यिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं।

वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, राजेश कुमार हिंगनकर एक नवंबर 2026 से अगले एक वर्ष तक मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें वर्ष 2024 में पहली बार इस पद पर संविदा नियुक्ति दी गई थी।

कै. मच्छर को यूई का प्रतिष्ठित सम्मान मुख्यमंत्री ने दी बधाई

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैप्टन स्मित मच्छर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिष्ठित सम्मान 'फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद' से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डॉ. यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कैप्टन स्मित ने असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए 170 से अधिक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और संभावित विमान हादसे को टाल दिया। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित का साहस, सेवा भावना और समर्पण प्रेरणादायी है।

एसडीएम के कार्यदायित्वों में बदलाव

नप्र, भोपाल : जिला प्रशासन ने प्रशासनिक कार्यसुविधा की दृष्टि से अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यदायित्वों में बदलाव किया है। कलेक्टर कार्यालय से 27 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, पीसी पांडे, अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, कोलार को कलेक्टर कार्यालय, भोपाल में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं, दीपक पांडे, अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, टीटी नगर को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ कोलार एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

चिकित्सा इकाइयों से 25 लाख पशुओं का उपचार

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार पशुपालकों और किसानों को घर पहुंच पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में संचालित 406 चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से अब तक 25 लाख से अधिक पशुओं का उनके घर पर उपचार किया जा चुका है।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत बनाने के निर्देश

सात जिलों में खुलेंगे वरिष्ठजन आश्रम



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई।

मंत्री ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत बनाने और उनका निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध

कराना विभाग की प्राथमिकता है। मंत्री ने केंद्रों में रिक्त पदों की पूर्ति और जिलों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 51 जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं। केंद्रों की गतिविधियों और मानव संसाधन की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के.जी.

तिवारी ने बताया कि प्रदेश में 89 वृद्धाश्रमों में 2,423 वरिष्ठजन रह रहे हैं। केंद्रीय अनुदान से 22 जिलों में 31 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं। देवास, शिवपुरी और श्योपुर में नए केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। झाबुआ, उमरिया, पाटुणा, बुरहानपुर, मऊगंज, अलीराजपुर और बड़वानी में वरिष्ठजन आश्रम शुरू करने के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं।

विदेश छात्रवृत्ति पोर्टल से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ : कृष्णा गौर



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बुधवार को विदेश छात्रवृत्ति एमपीओएम पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल डिजिटल सुशासन और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विभाग विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। पोर्टल के माध्यम से विदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में

उच्च शिक्षा, शोध और कोशल विकास के इच्छुक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी तथा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनेगी। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। पोर्टल का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें वैश्विक शोध और कोशल विकास के अवसरों से जोड़ना है।

किसानों की समृद्धि के लिए सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नर्मदा घाटी की सिंचाई परियोजनाओं से मालवा और निमाड़ में कृषि का विस्तार हुआ है। इसी तरह सतना और कटनी क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधाओं के विकास के

प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटनी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कटनी में किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर चिन्ता सोड, अश्वगंधा और काजू प्रसंस्करण जैसे नवाचार कर रहे हैं। प्राकृतिक और जैविक

खेती के साथ पशुपालन तथा मत्स्यपालन की भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवर्धन पूजन के अवसर पर प्रदेश के वृंदावन गांवों में गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इनमें श्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक गावों के पालकों को एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।

कार्रवाई वर्तमान में आयोग में लगभग 28,429 प्रकरण लंबित ...

महिला आयोग की संयुक्त बैठक में 51 प्रकरणों पर सुनवाई



शिकायतें प्रस्तुत की गईं। इनमें महिला प्रताड़ना के 15, दहेज

पारिवारिक विवाद के तीन प्रकरण शामिल थे।

मारपीट और संपत्ति विवाद के दो-दो मामले भी सामने आए। आयोग के अनुसार, मई 2026 में अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन के समय 31,825 शिकायतें लंबित थीं। इनके निराकरण के लिए प्रदेशभर में 17 संयुक्त बैठक आयोजित की गईं। इनमें 554 प्रकरणों की सुनवाई हुई और 143 का निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करने और

आवेदकों से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के आधार पर 3,243 शिकायतों का निराकरण किया गया। वर्तमान में आयोग में लगभग 28,429 प्रकरण लंबित हैं।

आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि महिलाओं की शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और संवेदशील निराकरण प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने और जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।